

तेल और गैस की बड़ी कंपनियों का एकीकरण ठीक नहीं ।

संदर्भ

सरकार देश की तेल और गैस की बड़ी कंपनियों के एकीकरण पर फरि से वचिार कर रही है । हालाँकि पिछले कुछ अनुभवों से पता चलता है कि एकीकरण से वांछति परणाम सामने नहीं आए हैं ।

परमुख बदि

- वतित मंत्री अरुण जेटली ने अपने चौथे बजट भाषण में फरि से एक एकीकृत तेल और गैस क्षेत्र के वचिार की समीक्षा परस्तुत कया था । हालाँकि पहली बार इस वचिार को अटल बहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 1998 में लाया गया था । परन्तु उस परस्ताव को एलपीजी, पेट्रोल, केरोसनि आदि जैसे ज़रूरी सामानों के वतिरण में एकाधिकार परदृश्य को बढ़ावा देने के आधार पर खारजि कर दया गया था ।
- उसके पश्चात् 2005 में यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई कृष्णामूर्ता समति ने उस परस्ताव को यह मानते हुये खारजि कर दया कि यह वचिार तेल और गैस क्षेत्र में परतसिपर्धा और मानवशक्ति को कम करेगा ।
- लेकिन वर्तमान में सरकार इस पर पुनः वचिार कर रही है । श्री जेटली ने इसके लयि पाँच परमुख कारण बताए हैं, जैसे - उच्च जोखमि उठाने की बेहतर क्षमता, बचत का लाभ उठाने, शेयरधारक मूल्य अधिक बनाने, नविश नरिणय बेहतर लेने और वशि्व स्तर पर अधिक सकषम होने ।

वलिय कहाँ तक उचति ?

- परन्तु वैशवकि स्तर पर नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि शीर्ष अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियों आकार में बहुत छोटी हैं । सरकारी फर्मों को मजबूत करने का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा है । 2007 में एयर इंडिया और भारतीय एयरलाइंस के वलिय के बाद वमिनन क्षेत्र को जो बड़ा झटका लगा था उससे वह अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई है ।
- तेल और गैस क्षेत्र में न्यूनतम राजनीतिक हस्तक्षेप और उदारीकरण ने एकीकरण के मुकाबले अधिक शेयरधारक मूल्य बनाने में बेहतर परदर्शन कया है ।
- ओएनजीसी द्वारा करज-ग्रस्त गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को सहायता दिए जाने के नरिणय को राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा बताया गया है । तेल कंपनियों पर ऐसे आरोपों और अक्षमताओं के मद्देनजर, कसिी एक इकाई को पूर्ण स्वायत्तता देने से राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो सकता है ।

रोज़गार

- एकीकरण को लेकर एक अन्य चति रोज़गार पैदा करने की है ।
- कृष्णामूर्ता समति ने पहले ही यह अनुमान लगाया था कि इस तरह के एकीकरण के परणामस्वरूप जनशक्ति में कमी होगी । ऐसे समय में जब सरकार नौकरी सृजन के साथ संघर्ष कर रही है, तब बड़ी कंपनियों के पुनर्गठन के कारण नौकरी के नुकसान का औचितिय साबति करना मुश्कलि होगा ।
- अधिक जोखमि लेने के लयि कसिी कंपनी की क्षमता उसके पास उपलब्ध पूंजी की मात्रा पर नरिभर करती है । भारत की सभी छह परमुख तेल कंपनियों के वत्तीय परदर्शन से पता चलता है कि उनके पास न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी है ।
- केवल आकार एकमात्र ऐसा कारक नहीं है जो ऑफशोर परयोजनाओं के अधगिरहण की सुवधि परदान करता है । आयरलैंड की टॉलो ऑयल, जसिके पास 3.62 अरब डॉलर की बाजार पूंजी है, कई देशों में स्थानीय तेल कंपनियों के साथ कंसोर्टिया बनाकर अपना वसितार कर रही है । इसलए, कंपनियों को अपने आकार की कमियों को दूर करने के लयि बेहतर रणनीति, तकनीकों और परबंधन के तरीकों पर ध्यान केंद्रति करनी चाहिए ।

परतसिपर्धा नहीं

- भारतीय तेल बाजार में आज कोई परतसिपर्धा नहीं है, और आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल का वर्चस्व है । अतीत में कड़ी परतसिपर्धा में लगाम लगाने का वमिनन और बैंकिग क्षेत्रों पर परतकूल परभाव को हम देख चुके हैं । इसलए, तेल और गैस क्षेत्र के एकीकरण से संबंधति कसिी भी नरिणय पर सावधानी से वचिार कया जाना चाहिए ।

